मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 110

01.12.2025 को उत्तर के लिए

उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण

110. श्री इमरान मसूद:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परितर्वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक शहरों जैसे कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ आदि में वायु गुणवत्ता सूचकांक में लगातार गिरावट दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई विशेष निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित किया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त निगरानी प्रकोष्ठ की संरचना और कार्यप्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन उपायों के परिणामस्वरूप प्रदूषण स्तर में कोई ठोस सुधार दर्ज किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (च): भारत सरकार ने देश भर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें से एक प्रमुख पहल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2019 में शुरू किया गया राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय, राज्य और शहरी स्तर पर स्वच्छ वायु कार्य योजना को क्रियान्वित करके 24 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 130 गुणवत्ता मानकों को पूरा न करने वाले और दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाना है।

उत्तर प्रदेश के 17 शहरों को शहरी कार्य योजना क्रियान्वित करने के लिए **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम** के अंतर्गत शामिल किया गया है। शहरी कार्य योजना के एक भाग के रूप में वायु गुणवत्ता को सुधारने

के उपायों का कार्यान्वयन करने के लिए एनसीएपी के तहत उत्तर प्रदेश को ₹2941.15 करोड़ की धनराशि जारी की गई है।

वायु गुणवत्ता को सुधारने के उपायों को क्रियान्वित करने के लिए सभी 17 शहरों ने शहर विशिष्ट स्वच्छ वायु गुणवत्ता कार्य योजनाएँ तैयार की हैं। ये योजनाएं, वायु प्रदूषण के स्रोत जैसे मिट्टी और सड़क की धूल, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, कचरा जलाना, निर्माण और तोड़-फोड़ की गतिविधियां तथा औद्योगिक प्रदूषण को लक्षित करती है।

उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित किए गए वायु गुणवत्ता प्रबंधन संबंधी उपायों में 3,666 किमी सड़कों को शुरू से आखिर तक पक्का करना, प्रति दिन 2375 किमी सड़क की मशीनीकृत सफाई, 2,800 एकड़ खुली जगहों को हरा-भरा करना और यातायात गलियारे के साथ 366 एकड़ भूमि को हरा-भरा बनाना शामिल है। इसके अलावा, भीड़ कम करने के लिए 25 यातायात जंक्शनों की भीड़भाड़ कम करके सुधार किया गया है, 37 श्मशान घाटों को स्वच्छतर इंधनों में बदला गया है या उन्हें प्रदूषण नियंत्रण करने वाले यंत्रों से सुसज्जित किया गया है, और 'माई भारत' प्लेटफॉर्म के ज़रिए युवाओं को शामिल करके पब्लिक आउटटीच और जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

सीपीसीबी ने उत्तर प्रदेश में 13 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की है, जिनमें 10 गंभीर और 3 अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र हैं। इन औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्य योजनाएँ तैयार की हैं और उन्हें संबंधित औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण को कम कम करने के लिए संबंधित उद्योगों द्वारा कार्यान्वित किया गया है। उत्तर प्रदेश में मौजूद 777 उद्योगों (17 लाल श्रेणी वाले) में से 690 उद्योगों ने ऑनलाइन निरंतर उत्सर्जन निगरानी तंत्र (ओसीईएमएस) इंस्टॉल किए हैं। सीपीसीबी ने उन 87 उद्योगों को निर्देश जारी किए हैं, जिन्होंने ओसीईएमएस इंस्टॉल नहीं किया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक प्रदूषण सहित स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संचालन समिति और अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत वायु गुणवत्ता निगरानी समिति (एक्यूएमसी) का गठन किया है और 17 शहरों ने वायु प्रदूषण कम करने के उपायों की योजना तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में शहर स्तरीय कार्यान्वयन समिति (सीएलआईसी) का गठन किया है।

वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के लिए उपाय किए गए 23 शहरों में से, 17 शहरों ने वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में अच्छी वायु गुणवत्ता वाले दिनों (एक्यूआई<200) में बढ़ोतरी दिखाई है। इसके अलावा, एनसीएपी के तहत किए गए प्रयासों से यूपी के सभी 17 लक्षित शहरों में वित्त वर्ष 2024-25 में वर्ष 2017-18 की अपेक्षा पीएम10 के स्तर में वायु प्रदूषण में 11.4-76.8% की कमी देखी गई है। तीन शहरों नामतः बरेली, वाराणसी और झांसी ने पीएम10 लेवल के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश के 17 लक्षित शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार की जानकारी **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

*****

अनुलग्नक-I

पीएम10 की सांद्रता में एनसीएपी के तहत उत्तर प्रदेश के 17 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार

राज्य	शहर	वार्षिक औसत पीएम10 सांद्रता माइक्रोग्राम/मी^{3} में (वित्त वर्ष 2017-2018 में)	वार्षिक औसत पीएम10 सांद्रता माइक्रोग्राम/मी^{3} में (वित्त वर्ष 2024-25 में)	वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 में % सुधार
उत्तर प्रदेश	बरेली	207	48	76.8
	वाराणसी	230	59	74.3
	फिरोजाबाद	247	100	59.5
	मुरादाबाद	222	96	56.8
	कानपुर	227	102	55.1
	आगरा	202	103	49
	गाजियाबाद	285	154	46
	रायबरेली	145	79	45.5
	झांसी	109	60	45
	लखनऊ	253	142	43.9
	इलाहाबाद	169	99	41.4
	नोएडा	229	149	34.9
	गोरखपुर	150	105	30
	गजरौला	204	148	27.5
	खुर्जा	195	159	18.5
	मेरठ	159	133	16.4
	अनपरा	175	155	11.4

पीएम10 सांद्रता के लिए वार्षिक राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (एनएएक्यूएस): 60 माइक्रोग्राम/मी^{3}